(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को फिल्म उद्योग से "केबल टी०वी०" और "डिश एंटीना" के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इन समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये 14 फरवरी, 1989 को एक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया है। इस समिति में राज्य सरकारों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, पायरेसी विरोधी कानून तथा उनका कार्यान्वयन, समिति द्वारा किये जाने वाले अध्ययन का एक मुद्दा होगा।

देश में जाली राशन कार्ड

*92. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाल में हजारों की तादाद में जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने हेतु कोई कानून बनाये जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राशन कार्ड स्वयं अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिये समय-समय पर जांच करते हैं। नागरिक पूर्ति विभाग ने हाल में उनसे अनुरोध किया है कि वे जाली राशन कार्डों/यूनिटों को छंटाई करने के लिये निरन्तर अभियान चलायें।

दिल्ली में प्रशासन द्वारा बिना शर्त सूचना के चुनी हुई उचित दर की दुकानों के पास दर्ज खाद्य कार्डों की जांच करने के लिये एक योजना बनाई गई थी। इस अभियान के परिणामस्वरूप 62,605 खाद्य कार्डों की जांच हो चुकी है और 14,853 मामलों में संबंधित व्यक्तियों को उन्हें खाद्य कार्ड जारी करते समय दिये गये पतों पर निवास करते नहीं पाया गया। इन मामलों में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल रोक दी गयी।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये उपयुक्त नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

Revision of Higher floor space Index in Bombay

*93. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have recently announced revised higher Floor Space Index for crowded localities including five star hotels, etc. in Bombay;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Central Government had sanctioned the revised FSI scheme of Bombay and if so, what was the advice given by the Central Government while sanctioning the higher FSI;

(d) whether the Central Government have prepared any guidelines regarding FSI of big cities and if so, what are the details thereof; and

(e) whether the Maharashtra Government's scheme is in accordance with these guidelines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) It is understood from the Government of Maharashtra that recently no announcement has been made in this regard.

(b) Does not arise.

(c) The fixation of Floor Space Index (FSI) is Part of Building regulation which is a State Government subject and hence the question of the Central Government sanctionig the same does not arise.

(d) No general guidelines regarding FSI in big cities have been issued by the Central Government.

(e) Does not arise.

Support Prices for Foodgrains

*94. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have started Special Foodgrains Production Programme for an increase in the production of foodgrains;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of districts of Madhya Prades covered under S.F.P.P.;

(d) whether it is a fact that the domestic prices of foodgrains are likely to go down which would adversely affect the farmers due to production boom in the foodgrains; and

(e) if so, what steps Government propose to take to support the prices of foodgrains and save the farmers from disaster?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) Yes, Sir. Special Foodgrains Production Programme (SFPP) was launched from Kharif 1988-89 in the 169 selected districts of the 14 selected States viz Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. Rice, wheat, maize, gram and arhar are the focus crops covered under this programme.

(c) 30 districts of Madhya Pradesh are covered under the SFPP.

(d) and (e) In order to ensure that farmers get a reasonable price for their produce, Government have declared minimum support prices for major commodities. FCI, NAFED and State Marketing Federations take up procurement and price support operations to ensure that price do not fall below the minimum fixed by the Government.

95. [*Transferred to the 9th May*, 1989]

Inclusion of Kerala under the Special Foodgrains Production Programmes 1989-90

*96. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the reasons for not including the State of Kerala in the Special Foodgrains Production Programmes of 1989-90 implemented by the Central Government; and

(b) the steps taken by the Central Government to supplement the efforts of the State Government in increasing the Rice production in Kerala?